आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 25.03.2026 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई।
- प्रदेश में मिलेट्स और कृषि गतिविधियां बन रहे सहकारिता के मजबूत आधार। रेशम, साइलेज और सामूहिक खेती से मजबूत हो रही किसानों की आर्थिकी।
- व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई।
- हरिद्वार में महिला और बाल चिकित्सा अस्पताल का संचालन शीघ्र शुरू होगा। महिलाओं और बच्चों को सरकारी दरों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

मंत्रिमंडल बैठक

प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश का पढ़ा। प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश पर राज्य मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यह संदेश राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बैठक में राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

सहकारिता

प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापक कार्य कर रही है। कृषि, मिलेट्स, रेशम उत्पादन, सब्जी क्रय, बायो–फर्टिलाइजर वितरण, साइलेज विक्रय और सामूहिक सहकारी खेती जैसी गतिविधियों से समितियों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है। प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत 214 क्रय केंद्रों के माध्यम से लगभग 53 हजार कुंतल मंडुवा की खरीद की गई है। इस खरीद पर सहकारी समितियों को 100 रुपए प्रति कुंतल सेवा शुल्क के आधार पर लगभग 53 लाख रुपए की आय हुई है। इसी तरह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से साइलेज का वितरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 181 केंद्रों के माध्यम से लगभग 20 हजार टन उच्च गुणवत्ता का साइलेज विक्रय किया गया है, जिससे सहकारी समितियों को लगभग 63 लाख रुपए की आय हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी संघ के माध्यम से टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में पांच सहकारी समितियों द्वारा किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद की जा रही है। इस साल अब तक किसानों से लगभग डेढ़ करोड़ मूल्य की सब्जियों की खरीद की जा चुकी है, जिन्हें बाजार में बेहतर मूल्य पर बेचा गया है। इस प्रक्रिया में सहकारी समितियों को लगभग 3 लाख की आय हुई है। इसके अतिरिक्त बायोफर्टिलाइजर के क्रय–विक्रय में भी सहकारी समितियां सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं, जिससे 14 समितियों को लगभग 68 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है।

सहकारिता क्षेत्र में रेशम उत्पादन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखंड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन ने लगभग 6 करोड़ 30 लाख मूल्य के रेशम उत्पादों का उत्पादन किया गया, जबकि करीब ढाई करोड़ के रेशम वस्त्रों का विक्रय किया गया। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह

रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का सीधा लाभ किसानों, काश्तकारों, कारीगरों और युवा उद्यमियों को मिले इसके लिये ठोस नीतियां तैयाकर कर धरातल पर उतारी जा रही है।

महापौर निरीक्षण

देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने शहर के कैनाल रोड पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत संचालित पाथ–वे अवसंरचना और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने पर विशेष जोर दिया। महापौर ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद स्थानीय नागरिकों को फुटपाथ से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी और आवागमन अधिक सुगम व सुरक्षित होगा।

व्यय वित्त समिति

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। इनमें देहरादून में रीठामंडी पेयजल योजना, तामली, चम्पावत में बहुग्राम पेयजल योजना मसूरी के क्यारखुली में मल्टी लेवल पार्किंग और रुद्रप्रयाग की बासुकेदार में तहसील बिल्डिंग के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। इसके अलावा रामनगर में बस पोर्ट निर्माण के अतिरिक्त कार्यों और यूपीसीएल के सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम में अतिरिक्त कार्यों को जोड़े जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राजकीय पॉलीटेक्निक नई टिहरी के कार्य में हॉस्टल सुविधा को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के निर्माण कार्य के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस कार्य के लिए चिह्नित स्थान सबसे उपयुक्त स्थल है और इसके लिए स्थल चयन समिति की रिपोर्ट भी लगाई जाए।

महिला अस्पताल

हरिद्वार में 200 बेड के महिला और बाल चिकित्सा अस्पताल का संचालन शीघ्र शुरू होने जा रहा है। अस्पताल में स्त्री प्रसूति वार्ड, मेडिसिन विभाग, नवजात शिशु इकाई, ट्रामा सेंटर, जनरल लेप्रोस्कॉपी सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और डायलिसिस जैसी उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी दरों पर मिल सकेंगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अस्पताल का संचालन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को बहुत कम खर्च पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।

पत्रकार प्रतिनिधिमंडल

उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भुवनेश्वर स्थित लोक भवन में ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच विकास, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, देहरादून की ओर से आयोजित प्रेस टूर के तहत पहुंचे 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक निदेशक संजीव कुमार सुन्द्रियाल ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. कंभमपति ने कहा कि ओडिशा और उत्तराखंड दोनों राज्यों में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की अपार संभावनाएं समान रूप से विद्यमान हैं। उन्होंने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम का उल्लेख करते हुए दोनों राज्यों की आध्यात्मिक समानताओं को रेखांकित किया। राज्यपाल ने मीडिया से तथ्यात्मक, सकारात्मक और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। इस दौरान पत्रकारों ने उत्तराखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

मधुमक्खी पालन

प्रदेश में मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार व आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास परिसर में मधुमक्खी के लगाए गए बक्सों से 101 किलोग्राम शहद निकाला गया। लोकभवन में स्थापित 15 मधुमक्खी बक्सों से पहले चरण में लगभग 41 किलोग्राम शहद प्राप्त हुआ। ये बक्से पुष्प प्रदर्शनी के दौरान परिसर में लगाए गए थे, जिनमें मेलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियां रखी गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहद निकालने की प्रक्रिया को देखा और विश्वास जताया कि उत्तराखंड का शहद भविष्य में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरेगा। वहीं, मुख्यमंत्री आवास परिसर में भी शहद निकालने के पहले चरण में लगभग 60 किलोग्राम शहद प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्र में '3–बी गार्डन' विकसित किए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाले शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं।